पत्र पेटेंट अपील

मुख्य न्यायधीश हरबंस सिंह और न्यायधीश गुरदेव सिंह, के समक्ष

रंजीत सिंह,-अपीलकर्ता.

बनाम.

हरियाणा राज्य, आदि,-प्रतिवादी.

पत्र पेटेंट अपील संख्या 335 ऑफ 1969.

24 मार्च 1971

पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषद अधिनियम (1961 का III) - धारा 5, 6, 8 और वी5-धारा-5 (2) (ए) (iii) के तहत हरियाणा में एक पंचायत समिति के लिए निर्वाचित सदस्य मार्केट समिति में ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता है -ऐसा सदस्य पंचायत समिति सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले मार्केट समिति का सदस्य नहीं रह जाता है-चाहे वह पंचायत समिति का सदस्य भी नहीं रह जाता है या इस पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। .

यह निर्धारित किया गया, कि पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषदों अधिनियम की धारा 5, जो पंचायत समिति के संविधान का निर्धारण करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके सदस्यों में से एक को मार्केट समितियों द्वारा चुना जाना चाहिए। ब्लॉक और ऐसी समितियों में से एक का निर्माता-सदस्य होना चाहिए। 1961 के अधिनियम III द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 8, ऐसे सदस्यों के कार्यालय का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित करती है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 15 यह प्रावधान करती है कि कोई सदस्य तुरंत सदस्य नहीं रह जाएगा और उसका कार्यालय रिक्त हो जाएगा यदि "वह धारा 6 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है"। हालाँकि, इस खंड में यह कहीं नहीं कहा गया है कि यदि कोई सदस्य मार्केट समिति का सदस्य नहीं रह गया है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा। अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) (ए) के खंड (iii) में निहित स्पष्ट प्रावधान के मद्देनजर, पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए कोई विवाद नहीं हो सकता है। मार्केट समितियों द्वारा समिति में लौटाया गया व्यक्ति उनके उत्पादक-सदस्यों में से एक होना चाहिए, लेकिन यह एक योग्यता है जिसे पंचायत समिति के चुनाव के समय पूरा करना होगा। अधिनियम में या यहां तक कि अधिनियम की धारा 6 और 15 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह बताता हो कि जैसे ही पंचायत समिति का निर्माता-सदस्य ब्लॉक में किसी भी मार्केट समिति का सदस्य बनना बंद कर देता है, ऐसी समिति में उसका कार्यकाल समाप्त होने पर, उसे अपना कार्यालय खाली करना होगा या वह अपनी सीट बनाए रखने के लिए अयोग्य हो जाएगा। धारा 6 के खंड (के) में उल्लिखित अयोग्यता धारा के पूर्ववर्ती खंड (जे) में उल्लिखित के समान है। इसलिए अधिनियम की धारा 5(2) (ए) (iii) के तहत हरियाणा में

पंचायत समिति के लिए निर्वाचित एक सदस्य, जो ब्लॉक में मार्केट समिति का प्रतिनिधित्व करता है, उसका सदस्य बनना बंद नहीं करता है और न ही वह पंचायत समिति में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि पंचायत समिति के सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले वह ब्लॉक में मार्केट समिति का सदस्य नहीं रह जाता है।

(पैरा 3, 5 और 6)

लेटर्स पेटेंट, माननीय श्री न्यायमूर्ति बाल तुली, दिनांक 30 मई,1969 द्वारा 1968 के सिविल रिट संख्या 1709 में पारित निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील।

एन . सी. जैन, एक वकील अपीलकर्ता की ओर से।

आर. के. जैन, एडवोकेट जनरल, हरियाणा, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

इस न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया:-

न्यायधीश गुरदेव सिंह.- पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 5 के तहत, एक ब्लॉक के लिए पंचायत समिति के सदस्यों में से एक को "ब्लॉक में मार्केट समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होना चाहिए, जिसका चयन ऐसी समितियों के सदस्यों द्वारा पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले उत्पादक सदस्यों में से किया जाता है।" 1964 में अमरीक सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) को पंचायत समिति, नीलोखेड़ी के लिए चुना गया था। समिति की उनकी सदस्यता की अवधि समाप्त होने से पहले, ब्लॉक में मार्केट समितियों के लिए नए चुनाव हुए, लेकिन उनकी वापसी नहीं हुई। हालाँकि, उन्होंने नीलोखेड़ी में पंचायत समिति के सदस्य के रूप में कार्य करना जारी रखा, जब कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास आयुक्त और हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग के सचिव ने सभी उप-विभागों को पत्र लिखा और हरियाणा राज्य में आयुक्तों ने कहा कि यदि मार्केट समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सदस्य किसी भी मार्केट समिति का सदस्य नहीं रह गया है, तो वह पंचायत समितियों या जिला के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य हो गया है। तदनुसार, उपायुक्त, करनाल ने माना कि अमरीक सिंह प्रतिवादी पंचायत समिति, नीलोखेड़ी का सदस्य नहीं रह सकता, और उसके द्वारा खाली की गई सीट पर नया चुनाव होना था। इसके बाद संबंधित मार्केट समितियों ने याचिकाकर्ता रणजीत सिंह को अधिनियम की धारा 5(2)(ए) (iii) के तहत पंचायत समिति, नीलोखेड़ी में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना।

(2) इससे पहले रणजीत सिंह के चुनाव को अधिनियम की धारा 10 के तहत उपायुक्त द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या OREO-PE-2-67/4690-96, दिनांक 18 अगस्त,

1967 में निहित निर्देशों को वापस ले लिया क्योंकि वह प्राप्त कानूनी सलाह के विपरीत थे। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने न केवल पंचायत समिति, नीलोखेड़ी के सदस्य के रूप में रणजीत सिंह के चुनाव को राजपत्रित करने से इनकार कर दिया, बल्कि 12 दिसंबर, 1967 की अपनी पिछली अधिसूचना को भी रद्द कर दिया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि अमरीक सिंह प्रतिवादी मार्केट समिति का सदस्य नहीं रह गया था। इस प्रकार व्यथित होकर, रणजीत सिंह संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय में आए और एक रिट के लिए प्रार्थना की जिसमें प्रतिवादी-अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उनके नाम को पंचायत समिति, नीलोखेड़ी के विधिवत निर्वाचित सदस्य के रूप में अधिसूचित करें। । उनकी याचिका को इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया है, उन्होंने लेटर्स पेटेंट के खंड (एक्स) में अपील की है।

(3) हमारे विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न है: "क्या कोई सदस्य अधिनियम की धारा 5(2)(ए)(iii) के तहत हरियाणा में एक पंचायत समिति के लिए चुने गए ब्लॉक में मार्केट समितियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंचायत समिति का सदस्य बनना बंद हो जाता है या बने रहने से अयोग्य हो जाता है जैसे कि सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पंचायत समिति के वह ब्लॉक में मार्केट कमेटी का सदस्य नहीं रह जाता है?

(4) आगे बढ़ने से पहले यह कहना उचित होगा की पंजाब के विषय में पंजाब समितियों और जिला परिषदों (संशोधन) अधिनियम 15 1968 की धारा 2 द्वारा इस मामले को शांत कर दिया गया है, जिसने मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में खंड (सी) जोड़ा है, इस प्रकार पढ़ते हुए:

"'उसके पास वह योग्यता समाप्त हो जाती है जिसके आधार पर उसे पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था।"

(5) अधिनियम की धारा 5, जो पंचायत समिति के संविधान को बताती है, इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि इसके सदस्यों में से एक को ब्लॉक के भीतर मार्केट समितियों द्वारा चुना जाना चाहिए और ऐसी समितियों में से एक का निर्माता-सदस्य होना चाहिए। अधिनियम की धारा 8, 1961 के अधिनियम III द्वारा संशोधित, ऐसे सदस्यों के कार्यालय का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित करती है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि एक सदस्य तुरंत सदस्य नहीं रह जाएगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा यदि "वह धारा 6 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है।" धारा 6 के संदर्भ में, हम पाते हैं कि यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि यदि कोई सदस्य मार्केट समिति का सदस्य नहीं रह गया है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा। इस धारा का खंड (के), जिस पर अपीलकर्ता की ओर से भरोसा किया गया है, इस प्रकार पढ़ता है: –

“कोई भी व्यक्ति प्राथमिक सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि ऐसा व्यक्ति –

(के) सदस्य के रूप में निर्वाचित या सहयोजित होने के लिए अयोग्य है।

(6) एक मार्केट समिति का सदस्य पंचायत समिति का सदस्य बन सकता है, इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति ब्लॉक के भीतर एक मार्केट समिति का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह सदस्य के रूप में अपनी सीट बरकरार रखने से अयोग्य हो जाता है। समिति के अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2)(ए) के खंड (iii) में निहित स्पष्ट प्रावधान के मद्देनजर, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए मार्केट समितियों द्वारा समिति में लौटाया गया व्यक्ति उनके उत्पादक-सदस्यों में से एक होना चाहिए, लेकिन यह एक योग्यता है जिसे उसे पंचायत समिति के चुनाव के समय पूरा करना होगा। अधिनियम में या यहां तक कि अधिनियम की धारा 6 और 15 में भी कुछ नहीं है, जो यह निर्धारित करता है कि जैसे ही पंच-सदस्य समिति का निर्माता-सदस्य ऐसी समिति में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर ब्लॉक में किसी भी मार्केट समिति का सदस्य बनना बंद कर देता है, उसे अपना कार्यालय खाली करना होगा या वह अपनी सीट पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। हमारी राय में, धारा 6 के खंड (के) में उल्लिखित अयोग्यता-उस खंड के पूर्ववर्ती खंड (जे) में उल्लिखित के समान है, जो यह प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति प्राथमिक सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि ऐसा व्यक्ति "अपने चुनाव को इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या नगर पालिकाओं, पंचायतों या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित किसी अन्य अधिनियम के तहत रद्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप नगर समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की सदस्यता से अयोग्य हो जाता है।

(7) पंजाब पंचायत समितियाँ और जिला परिषद (चुनाव याचिका) नियम, 1961, जो स्वीकार्य रूप से हरियाणा राज्य पर भी लागू होते हैं के नियम 10 के उप-नियम (2) के तहत, निर्धारित प्राधिकारी को चुनाव याचिका का निपटारा करते समय यह पता लगाने की आवश्यकता होती है कि क्या कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है या साबित नहीं हुआ है और आगे भी उन व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करने के लिए जो मुकदमे में साबित हो चुके हैं कि वे किसी भी भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं या इसमें शामिल होने या बढ़ावा देने के लिए दोषी हैं और वह अवधि तय करें जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पंचायत समितियों या जिला परिषदों के सदस्य बनने के लिए अक्षम रहेंगे। । किसी भी भ्रष्ट आचरण के सबूत पर चुनाव को रद्द करते हुए, निर्धारित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि न केवल संबंधित सदस्य भ्रष्ट आचरण का दोषी है, बल्कि अन्य भी दोषी हैं। इसके बाद, वह उन सभी को एक विशिष्ट अवधि के लिए पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य बनने से अयोग्य घोषित कर देता है। अधिनियम की धारा 6 के खंड (जे) में उल्लिखित अयोग्यता केवल उस सदस्य के मामले को कवर करती है जिसका चुनाव रद्द कर दिया गया है न कि अन्य जो ऐसी प्रथाओं के दोषी हो सकते हैं या मिलीभगत कर सकते हैं उसी पर या उसे बढ़ावा देना। ऐसे अयोग्य व्यक्तियों (उस सदस्य के अलावा जिसका चुनाव रद्द कर दिया गया है) के मामले को कवर करने के लिए खंड (के) का इरादा है।

(8) अधिनियम की धारा 15, जिसका शीर्षक "सीटों को खाली करना" है, उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जिनमें पंचायत समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यालय में प्रवेश करने के बाद तुरंत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नहीं रहेगा। इसके अनुसार,यदि कोई सदस्य धारा 6 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है, या बिना अनुमति के पंचायत समिति की लगातार तीन से अधिक साधारण बैठकों से अनुपस्थित हो जाता है, तो वह तुरंत अपनी सीट खाली छोड़ देता है। यदि विधायिका का इरादा होता कि मार्केट समितियों के उत्पादक-सदस्यों में से समिति में लौटा एक सदस्य ऐसी समिति का सदस्य नहीं रहने पर अपनी सीट खाली कर देता, तो विधायिका इसमें विफल नहीं हो सकती थी और धारा 15 को अधिनियमित करते समय ऐसा कह देती।

(9) इस प्रकार हम पाते हैं कि अपीलकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं था। अपील लागत सहित खारिज की जाती है।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा